

जी भी कहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में क्या होता है, हमें पता नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा मैं आप पर ज्यादा टोका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हम इंटेरेस्टिड हैं कि हमारे लोगों को न्याय और उचित काम मिले। हम प्रधान मंत्री जी आपसे विनती करते हैं कि आज आप आशवासित करें और हमें यह बतायें कि ओ.एम. के ऑर्डर्स कब निकलेंगे और इस देश में हमारे दलितों पर सर्विसेज में जो अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय देने का काम आप करेंगे, मैं आपसे इतनी ही विनती करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, श्री माणिकराव गावित, श्री रामदास आठवले और के.एच. मुनियप्पा को इसी विषय पर सूचना दी गई है। मैं उन्हें इस मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति देता हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हां, मैंने उन्हें इस मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): प्रदान मंत्री जो ओ. एम. विदडा करो। ...(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिन्डे जी ने जो सवाल उठाया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार में और प्रतिपक्ष में उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। हम चाहते हैं कि परिगणित जातियों और परिगणित जनजातियों की स्थिति में सुधार हो। सेवाओं में उनके साथ पूरा न्याय हो और न्याय का अर्थ यह है कि अभी तक जो अन्याय हुआ है या अभी तक जो उपेक्षा हुई है उसका परिमार्जन करने का रास्ता भी निकाला जाए, इसीलिए नीतियां बनी हैं। लेकिन उन नीतियों को चुनौती दी जाती है, मामले अदालत में जाते हैं। सदन को स्मरण होगा कि सरकार दो बार संविधान संशोधन विधेयक ला चुकी है, और वह सर्वसम्मति से पास हुआ था क्योंकि इस पर कोई मतभेद नहीं है। तीसरा जो मुद्दा आपने उठाया है, जो सवाल अभी बाकी है, नौकरियों से संबंधित है, वह सरकार के सामने विचाराधीन है।

मगर कठिनाई उसमें यह पैदा हो रही है कि मामाल अदालत में भी है, कांस्टीट्यूशन बैंच के सामने भी है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां से अनुकूल फैसला हो। सरकार वचनबद्ध है। हम तो संसद के इस बजट सत्र के पहले ही इस तरह का विधेयक लाना चाहते थे, लेकिन हम फिर से प्रयास कर रहे हैं और आपका समर्थन उसमें आवश्यक है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महाराष्ट्र सरकार द्वारा मजदूर विरोधी नीति अपनाई जा रही है। ...(व्यवधान) मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रधान मंत्री बैठे हैं, मुझे उनसे जवाब चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी हर किसी मामले पर जवाब देने हेतु खड़ा होने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार पांच दिनों से बिहार के सवाल पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ बिहार इस देश का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कल भी छ: दलितों की हत्या सासाराम जिले में कर दी गई। आज से पांच दिन पहले जंगलटोला में अति-पिछड़े और दलितों के 213 घर जला दिए गए और एक बच्चे को आग में फेंक दिया गया। वर्तमान अपराधी जो बिहार में पल रहे हैं, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण अपराधी बिहार सरकार की छत्रछाया में पल रहे हैं। जो हालात बिहार के हैं, पंचायत चुनाव जब से शुरू हुए हैं और अभी तीन चरण पंचायत चुनावों के बाकी हैं, 200 से ऊपर हत्याएं हो गई हैं। और कितनी हत्याएं होंगी, यह कहना मुश्किल है लेकिन संपूर्ण बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में दहशत का वातावरण न हो, गोलियां न चल रही हो, जाति और मजहब के बीच में झगड़े न हुए हों, उन्माद न फैलाया जा रहा हो - सिर्फ अपराधियों द्वारा ही नहीं, सरकारी तन्त्र के द्वारा भी और सरकार के वर्कर्स द्वारा भी, सरकार के मंत्रियों और विधायकों द्वारा भी खुलेआम बंदूक और राइफल से गोलियां चलाई जा रही हैं और प्रत्याशियों पर गोली चलाकर उनको कत्ल किया जा रहा है। एक मंत्री को इलैक्शन कमीशन द्वारा वहां से जो रोका गया लेकिन वे मंत्री वहां जाने से बाज में नहीं आए और उल्टे वहां जाकर मंत्री ने राइफल से गोली चलाकर हत्या की। परिस्थिति इतनी विस्फोटक है कि वहां कोई भी जन-प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और मैं बता नहीं सकता कि वहां क्या परिस्थिति है।...(व्यवधान)